

मकुेश कुडर डनन, टिप्पणीकार

लू लगने से बीते पांच महीने में 20 लोगों की मौत: सरकार

इस साल एक मार्च से अब तक देश भर में लू लगने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,853 मामले सामने आए हैं। लू लगने से सबसे अधिक संख्या में लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई, जबकि लू लगने के सर्वाधिक मामले तेलंगाना में सामने आए। सरकार की ओर से मंगलवार को लोकसभा में ये आंकड़े पेश किए गए। आंकड़ों के अनुसार, लू से महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में चार, तेलंगाना और ओड़ीशा में दो-दो तथा तमिलनाडु में एक व्यक्ति की जान गई। तेलंगाना में लू (हीटस्ट्रोक) के सबसे अधिक 915 मामले सामने आए, इसके बाद पश्चिम बंगाल (733), छत्तीसगढ़ (660), आंध्र प्रदेश (540) और झारखंड (409) का स्थान रहा। मंत्री के जवाब में बताया गया कि दिल्ली में लू लगने के 32 मामले सामने आए और कोई मौत नहीं हुई। (ए)

विशेष
जनसत्ता | 5 अगस्त, 2026

सात माह में 77 हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं

पंकज रोहिला

राजमार्ग का सफर कम खतरनाक नहीं है। इन मार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ रही गाड़ियों के बीच जान-माल का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस साल के शुरुआती सात माह के आंकड़े इन बुरे हालातों की गवाही दे रहे हैं। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जुलाई 2026 तक केवल राजमार्ग पर 77234 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में 32771 लोगों की जान गई है और हादसों की वजह से 89560 वाहन चालकों को चोटें आई हैं।

केवल सात माह का यह आंकड़ा करीब-करीब बीते साल के आंकड़े की रफ्तार पर है। क्योंकि वर्ष 2025 में ऐसी करीब कुल 1,43,526 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन दुर्घटनाओं में मौतों का कुल आंकड़ा 62212 और घायल होने वाले लोगों की संख्या 1,60,224 थी। केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि बीते पांच साल से राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में चोटें खाने वाले वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2022 कुल दुर्घटना 1,51,997 थी। इन दुर्घटना में 61038 लोगों की जान गई थी और 1,44,352 लोगों के दुर्घटना में चोटें आई थीं। जिन राज्यों में इस तरह के हादसों सबसे अधिक सामने आ रहे हैं, उन राज्यों में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं।

25 से 35 की उम्र वाले ही है हादसों के सबसे अधिक शिकार : रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई



केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जुलाई 2026 तक केवल राजमार्ग पर 77234 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में 32771 लोगों की जान गई है और हादसों की वजह से 89560 वाहन चालकों को चोटें आई हैं।

केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि बीते पांच साल से राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में चोटें खाने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2022 कुल दुर्घटना 1,51,997 थी। इन दुर्घटना में 61038 लोगों की जान गई थी और 1,44,352 लोगों के दुर्घटना में चोटें आई थीं।

रिपोर्ट

2026 तक अधिक शिकार होने वाले वाहन चालकों की औसतन आयु 25-35 वर्ष के बीच है। यह आंकलन दुर्घटना के बाद राज्य सरकारों की ओर से उपलब्ध कराए गए कैशलेस सुविधा के आंकड़े से सामने आया है।

जुलाई तक 18 वर्ष से कम आयु के 1570 लोग शामिल हैं, यह आंकड़ा बीते वर्ष 2025 में 2764 था, 18 से 35 वर्ष की आयु के 4690 जो कि बीते वर्ष में 7640 था और 25 से 35 आयु के 7285 जो कि बीते वर्ष में 12353 दर्ज किया गया था। सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों का आंकड़ा देखें तो इस साल जुलाई 2027 तक सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों की है। इस साल अब तक ऐसे 7097 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 35 से 45 वर्ष की आयु वाले 5926 लोग और

60 वर्ष की आयु वाले 4232 लोग शामिल हैं। 289 ऐसे लोगों की भी मौत हुई है, जिनकी आयु पता ही नहीं चल पाई है।

1730 दावों का है निपटारे का इंतजार : केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटना और कैशलेस उपचार के लिए किए गए दावों में से इस साल 1730 दावों की मंजूरी का इंतजार है। जुलाई तक इस योजना के तहत कुल 12727 कुल दावे किए गए थे, इन दावों में से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 9601 दावों को अनुमोदित किया गया था। इन दावों में से 7871 दावों का निपटारा केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका है। इन दावों में पीड़ितों को 10.1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ऐसे सबसे अधिक दावे गुजरात, मध्य प्रदेश और असम राज्यों की ओर से जुलाई तक सरकार के पास किए गए हैं।

सर्वेश कुमार

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कतर के बाद हीलियम के निर्यात पर चीन की तरफ से लगाई गई

पाबंदी का असर देश में खतरा लगातार मंडरा रहा है। अक्रिय गैस होने की वजह से शीतलक के तौर पर एमआरआइ (मेग्नेटिक रिजॉनेंस इमेजिंग), सेमीकंडक्टर चिप, मिसाइल, राकेट, परमाणु ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वैश्विक आपूर्ति में कमी और निर्यात पर भारत की शत प्रतिशत निर्भरता के कारण खतरा बरकरार है। हालांकि इसके कुछ वैकल्पिक उपायों की तलाश जारी है, बावजूद इसके अगर लंबे समय तक हालात नहीं सुधरते तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

चीन ने हाल ही में हीलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है जबकि कतर पर हुए हमलों के कारण पहले ही हीलियम की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कतर, वैश्विक हीलियम का लगभग एक तिहाई उत्पादन करता है, लेकिन उसके गैस बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण उत्पादन रुक गया है। होर्मुज जलमार्ग के अवरुद्ध होने की वजह से आपूर्ति शृंखला के प्रभावित होने से विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सुपरकंडक्टिंग चुंबक को ठंडा करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव ऊतकों की 3 डी इमेजिंग के जरिए स्थितियों का निदान करने में मदद करते हैं। सुपरकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है



कतर, वैश्विक हीलियम का लगभग एक तिहाई उत्पादन करता है, लेकिन उसके गैस बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण उत्पादन रुक गया है। होर्मुज जलमार्ग के अवरुद्ध होने की वजह से आपूर्ति शृंखला के प्रभावित होने से विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञ के मुताबिक, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी मिसाइल की तरह हवा से टक्कर या घर्षण से बचाने के लिए राकेट में भी हीलियम वैल्विंग का इस्तेमाल किया जाता है। सुनीता विलियम्स सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को भी हीलियम लीक की समस्या होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अधिक दिनों तक रुकना पड़ा था।

जो शून्य प्रतिरोध (पदार्थ में धारा प्रवाह के अवरोध के रूप में परिभाषित) के साथ विद्युत का संचालन करता है। हालांकि, ऐसा करने के लिए चुंबकों को अत्यंत कम तापमान पर काम करने की जरूरत होती है। हीलियम इन चुंबक के लिए आदर्श शीतलक है क्योंकि इसका द्र्व्यनांक किसी भी तत्व से सबसे कम(-268.9 डिग्री सेल्सियस) है। इस तापमान या उससे कम पर, हीलियम द्रव अवस्था में होता है और इसका इस्तेमाल एमआरआइ स्कैनर के लिए किया जाता है। नाभिकीय बिजली संयंत्र में भी नाभिकीय प्रतिक्रिया (न्यूक्लियर क्रॉस

सेक्शन सबसे कम) की दर को कम करने के लिए गैसीय जबकि उच्च तापमान को नियंत्रित करने के लिए द्रवित हीलियम का इस्तेमाल होता है। हीलियम का अध्ययन कर रहे हैं एक इंजीनियरिंग कालेज के विशेषज्ञ के मुताबिक, एमआरआइ, सुपरकंडक्टिंग ब्लंटम ड्रिवाइसेज (स्क्रिबड) सहित कई और जरूरी कार्यों में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रक्षा उपकरणों खासतौर पर मिसाइल में थर्मल इंसुलेंटिंग टाइल की वैल्विंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस्तेमाल के दौरान हवा से होने वाले टकराव और घर्षण का असर न हो।

आस्था



हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी पर उमड़ें श्रद्धालु।

पांच साल के हर तीन में से एक बच्चे का कद सामान्य से कम

उभरी है। वहीं बच्चों में होने वाली कमजोरी व दुबलेपन की समस्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। यह बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत शून्य से पांच साल के बच्चे के विकास की निगरानी की जाती है। इस निगरानी के दौरान जून 2026 तक देशभर में 66814577 (98 फीसद) बच्चों की माप ली गई। इस जांच के दौरान 29 फीसद बच्चे सामान्य कद से छोटे पाए गए। इन बच्चों की स्थिति गंभीर या मध्यम स्तर मिली। वहीं 11 फीसद बच्चों का वजन सामान्य से कम मिला। इसमें भी स्थिति बहुत ज्यादा या काफी कम वजन

पाई गई, जबकि पांच फीसद बच्चों में सामान्य से ज्यादा वजन की समस्या पाई गई। इन बच्चों में मोटापा व ज्यादा वजन गंभीर रूप से पाया गया। वहीं तीन फीसद बच्चों में कमजोरी व दुबलेपन की समस्या पाई गई। एम्स के बाल चिकित्सा विभाग, एंडोक्रिनोलॉजी की प्रोफेसर डा. वंदना जैन ने बताया कि बच्चे का कद सामान्य तौर पर न बढ़ने, वजन कम रहने या दुबलापन होने के पीछे कुपोषण एक बड़ा कारण हो सकता है। देश के काफी बच्चों में यह समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा यह देखने को मिल रहा है कि जन्म के समय बच्चे का वजन सामान्य से कम होता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो ग्राम तक रहना चाहिए, लेकिन करीब 30 से 35 फीसद बच्चों में यह वजन कम पाया जाता है।

अस्सी के दशक से बदलने लगा कांवड़ मेले का स्वरूप

सुनील दत्त पांडेय

श्रावण माह में 80 के दशक से पहले कांवड़ मेले का प्रचलन नहीं था। फाल्गुन मास में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिनों ही कांवड़ यात्रा का महत्व था और हरिद्वार में बिजनौर, मुद्रावाबाद, बदायूं, बरेली से कावड़ यात्री हरिद्वार फाल्गुन मास में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के समय गंगाजल भरने आते थे और तभी गंगाजल की अद्भुत यात्रा निकलती थी, बड़े ही शांत भाव से और तब कांवड़ियों की तावाद भी बहुत कम होती थी और महाशिवरात्रि से 10-12 दिन पहले ही कांवड़िए हरिद्वार आते थे और जल भरकर पैदल जाते थे, कोई बड़ा ताम-झाम भी नहीं होता था।

1980 के दशक में हिंदू समाज के एक वर्ग में धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। सावन माह में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शुरू में तो कांवड़ यात्रा में बहुत कम श्रद्धालु आया करते थे, परंतु बाद लोग बढ़ते गए। कांवड़ यात्रा को ज्यादा बढ़ावा देने में फिल्म निर्माता निर्देशक गुलशन कुमार की फिल्म, गाने, भजन आदि को श्रेय दिया जा सकता है। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर कई भजन और गीत बाजार में उतारे। गुलशन कुमार खुद भी कांवड़ लेकर हरिद्वार आया करते थे।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राम मंदिर का अयोध्या में ताला खुला और राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, उससे हिंदुओं के इस वर्ग में कांवड़ यात्रा को लेकर और अधिक आकर्षण बढ़ा, इसी बीच कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी तेजी से बदलने लगा जहां एक और कांवड़ यात्रा में पैदल चलने वाले कांवड़ियों की तावाद बहुत अधिक होती थी, डाक कांवड़ का दौर चला। उसी के साथ भारी भरकम डीजे भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे।

1996 के आसपास पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। उस दौर में हरिद्वार में रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कांवड़ियों को नियंत्रित करने

वर्ष 1980 के दशक में हिंदू समाज के एक वर्ग में धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। सावन माह में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शुरू में तो कांवड़ यात्रा में बहुत कम श्रद्धालु आया करते थे, परंतु बाद लोग बढ़ते गए।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राम मंदिर का अयोध्या में ताला खुला और राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, उससे हिंदुओं के इस वर्ग में कांवड़ यात्रा को लेकर और अधिक आकर्षण बढ़ा, जहां एक और कांवड़ यात्रा में पैदल चलने वालों की तादाद बहुत अधिक होती थी, डाक कांवड़ का दौर चला।

श्रद्धा

के लिए गंगा नहर के साथ-साथ बनी हुई सड़क को कावड़ पटरी के रूप में विकसित किया। 2012 में हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी ने कांवड़ियों के वाहनों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए बैरागी कैप के बड़े मैदान को पार्किंग के रूप में तब्दील किया और यह प्रयोग बेहद सफल रहा। तब से दक्षदीप और बैरागी कैप कांवड़ियों की सबसे बड़ी पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कांवड़ियों से भावनात्मक रिश्ता बनाने की जोरदार पहल शुरू की और उन्होंने पिछले तीन सालों से लगातार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने और उनके चरण धोकर उनका सम्मान करने और साथ ही उन्हें स्वयं अपने हाथ से भोजन परोसने की पहल की। ताकि कांवड़ियों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके। इसके अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत डा. रविंद्र पुरी महाराज ने भी कावड़ यात्रा में प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस बार हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर वैशित ने कांवड़ मेला को व्यवस्थित करने के लिए कई नई पहल शुरू की।

दे

आत्मविश्वास में कमी और सामाजिक या शारीरिक विकास से जुड़ी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा इन बच्चों में उम्र के साथ वजन का न बढ़ना भी देश में मोटापे से दोगुनी बड़ी समस्या बनकर

समस्या



इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ ‘रेड कार्नर नोटिस’ जारी किए गए हैं।

‘रेड कार्नर नोटिस’ दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध होता है, ताकि उसके प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण कराने या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई की

वर्ष 2019 से 2026 (जुलाई तक) के बीच वापस लाए गए भगोड़ों में से नौ लोग आर्थिक अपराधों, 17 लोग आतंकी मामलों, 42 लोग संगठित आपराधिक गतिविधियों, 62 लोग हत्या, डकैती और हिंसक अपराधों, 53 लोग यौन अपराधों और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों, 16 लोग मादक पदार्थ की तस्करी, 12 लोग तस्करी और जाली नोट वगैरह, 18 लोग मानव तस्करी और 45 लोग अन्य अपराधों के मामलों में वांछित थे।

पदार्थ की तस्करी, 12 लोग तस्करी और जाली नोट वगैरह, 18 लोग मानव तस्करी और 45 लोग अन्य अपराधों के मामलों में वांछित थे। बयान में कहा गया है कि इंटरपोल द्वारा ‘रेड कार्नर नोटिस’ जारी करने की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 40, 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112, और 2026 में अब तक 182 ‘रेड कार्नर नोटिस’ जारी किए गए हैं।

सख्ती

जनसत्ता ब्यूरो

सरकार ने मंगलवार को कहा कि पिछले सात वर्षों में 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाया गया है। यह संख्या प्रतिवर्ष औसतन करीब 40 है जो 2004-13 की अवधि की तुलना में 10 गुना अधिक है, जब हर साल करीब चार भगोड़ों को वापस लाया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भगोड़ों की 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है।

बयान में दावा किया गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भगोड़ों को वापस लाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी, जबकि मोदी सरकार ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। 2019 से 2026 (जुलाई तक) के बीच वापस लाए गए भगोड़ों में से नौ लोग आर्थिक अपराधों, 17 लोग आतंकी मामलों, 42 लोग संगठित आपराधिक गतिविधियों, 62 लोग हत्या, डकैती और हिंसक अपराधों, 53 लोग यौन अपराधों और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों, 16 लोग मादक

